जून 2020
खंड - XXXVI | अंक - II

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

इस अंक में

- कोविड–19 के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारत का टैरिफ फ्रेमवर्क: प्रमुख समस्याएं और नीतिगत सुझाव
- दोराहे पर भारतीय मोटर वाहन उद्योग
- जीसीसी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध: व्यापार, प्रवासन और प्रेषण
- कोविड–19 के दौरान व्यापार अनिश्चितता से निपटना

तिमाही प्रकाशन:

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ परेड,
मुंबई – 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in

www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

कोविड–19 के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था

कोविड–19 की वजह से मांग के साथ–साथ आपूर्ति क्षेत्र में आई कमी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। तालाबंदी के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान और यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप उत्पादन में भारी नुकसान होगा। भारत में आपूर्ति क्षेत्र में जो नुकसान हुए उनका कारण फैक्ट्री बंद होना, लेबर की कमी, इनपुट आपूर्ति में व्यवधान और कॉर्पोरेट्स और एमएसएमई के लिए नकदी प्रवाह में कमी आना रहा। जबकि मांग के क्षेत्र में हुए नुकसान का कारण ज़रूरत के अनुसार खर्च, मांग में गिरावट, आय और रोजगार में कमी और बाजार भावनाओं का कमजोर होना रहा। भारत सरकार के आकलन के अनुसार, भारत की वृद्धि वर्ष 2019–20 में 4.2% से गिरकर 2020–21 में कम हो जाने की आशंका है। यदि यह महामारी और फैलती है और इसकी वजह से व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा आती है तो ये प्रभाव लंबे समय तक बने रहेंगे।

वर्ष 2020 में वैश्विक वृद्धि –5.2% से –4.9% तक रहने के आसार हैं। वर्ष 2021 में, आर्थिक वृद्धि में सुधार होकर इसके 4.2% से 5.4% तक हो जाने का अनुमान है (तालिका 1)। हालांकि, ये सभी आकलन इस अनुमान पर आधारित हैं कि यह महामारी वर्ष 2020 के उत्तरार्ध में कुछ कम हो जाएगी और रोकथाम के लगातार प्रयासों से समाप्त हो जाएगी। व्यापार के संबंध में, विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि कोविड–19 महामारी की वजह से दुनियाभर में सामान्य आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, अतः वर्ष 2020 में विश्व मर्चेंडाइज़ 13% से 32% के बीच रह सकता है।

तालिका 1: भारत और विश्व के लिए विकास के अनुमान

पूर्वानुमानकर्ता	जारी करने का माह	वृद्धि का पूर्वानुमान (%)			
		विश्व		भारत	
		2020	2021	2020	2021
विश्व बैंक	जून–20	–5.2	4.2	–3.2	3.1
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	जून–20	–4.9	5.4	–4.5	6.0
एशियाई विकास बैंक	जून–20	–	–	–4.0	5.0

स्रोत: संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां

भारत का निर्यात क्षेत्र: भारत का मर्चेंडाइज़ निर्यात अप्रैल 2020 के (–) 60.3% (वर्ष–दर–वर्ष) से गिरकर मई 2020 में (–) 36.5% (वर्ष–दर–वर्ष) 19.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। मर्चेंडाइज़ आयात में भी अप्रैल 2020 के (–) 58.7% (वर्ष–दर–वर्ष) के मुकाबले मई 2020 में (–) 51.1%

(वर्ष–दर–वर्ष) गिरावट आई और यह 22.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा (चार्ट 1)। अप्रैल–मई 2020 के दौरान, भारत का निर्यात 32.2 बिलियन यूएस डॉलर और आयात 39.3 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। तदनुसार, मर्चेंडाइज़ व्यापार घाटा अप्रैल–मई 2019 के 30.7 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर अप्रैल–मई 2020 में 9.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। जहां तक भारत के निर्यातों की दिशा का संबंध है, भारत के निर्यातों का 49% एशिया को और उत्तरी 17% अमेरिका को जाता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, 2020 में, एक आशावादी परिदृश्य में एशिया से 11.8% और उत्तरी अमेरिका से 14.5% के आयात की गिरावट होने की आशंका है, जबकि नकारात्मक परिदृश्य से देखें तो, आयात में क्रमशः 31.5% और 33.8% की गिरावट का अनुमान है। तदनुसार, 2020–21 में भारत से निर्यातों में सुधार मुश्किल प्रतीत होता है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020–21 में अब तक (15 मई तक) 9.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 487.0 बिलियन यूएस डॉलर – 12 महीनों के आयातों के समतुल्य हो गया है।

बाहरी मोर्चे पर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) बहिर्वाह के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। तथापि, रुपये ने उभरते बाजार की अपनी समकक्ष मुद्राओं की तुलना में विदेशी मुद्रा बाजार में बने रहने के लिए लचीलापन प्रदर्शित किया है। मार्च 2020 में भारतीय रुपये का मूल्य एक यूएस डॉलर की तुलना में 76.2 INR / USD से घटकर अप्रैल 2020 में 74.3 रुपये प्रति यूएस डॉलर रह गया।

घरेलू आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट से आयातों में काफी कमी आई है। इससे 2020–21 की पहली तिमाही में भारत के चालू खाते में थोड़ा अधिशेष बन सकता है। भारत का चालू खाता विदेशी ऋण चुकौतियों के निम्न स्तर से भी समर्थित है।

भारत का क्षेत्रवार परिदृश्य: ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही इसने व्यवसायों और रोजगार की स्थिरता पर भी प्रश्न चिह्न खड़े कर दिए हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल और अपेरल, परिवहन, पर्यटन, निर्माण और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रोज़मर्रा के संचालनों में व्यवधान के कारण दबाव रहने के आसार हैं। कोविड–19 के बाद ई–कॉमर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी (विशेष रूप से रिमोट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और आईसीटी सेवाएं और ऑनलाइन सामग्री प्रदाता), साइबर सुरक्षा और हेल्थकेयर और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में वृद्धि हुई है।

भारत द्वारा प्रमुख नीतिगत उपाय: कोविड–19 महामारी के चलते दुनियाभर में राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय करने पड़े हैं। भारत ने भी 26 मार्च, 2020 से लिक्विडिटी और वृद्धि को बढ़ाने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय पैकेजों की श्रृंखलाबद्ध तरीके से घोषणा की है। अर्थव्यवस्था को कोरोनो वायरस के झटके से बचाने के लिए भारत सरकार ने 12 मई, 2020 को 20.97 लाख करोड़ (भारत के जीडीपी का लगभग 10%) के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसका नाम 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' है। इस पैकेज का अंतर्निहित उद्देश्य भारत के उत्पादन में ऐसी गुणवत्ता लाने पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका निर्यात वैश्विक स्तर पर किया जा सके। इस तरह भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाया जा सके। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज में 38.2% हिस्सा भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणाओं के जरिए रहा। इस घोषणा के बाद, 22 मई, 2020 को आरबीआई ने अपनी नीतिगत

चार्ट 1: भारत का व्यापार और वृद्धि

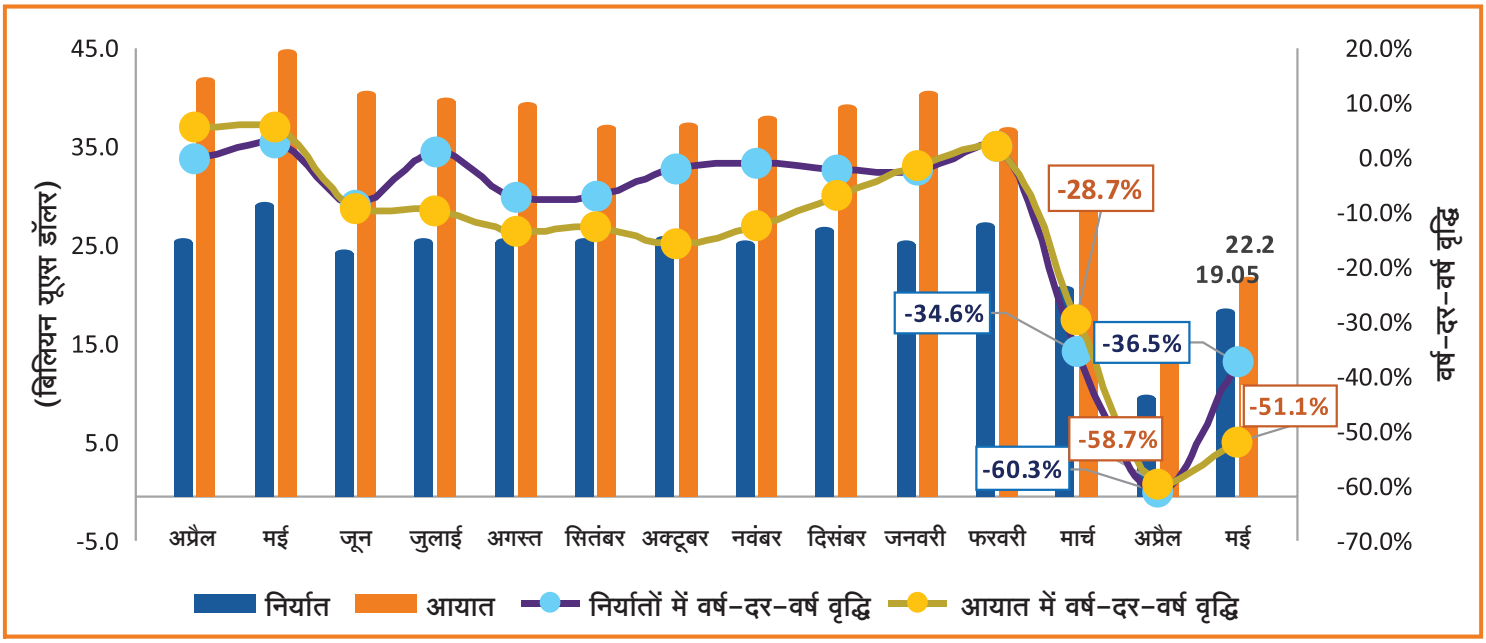

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

दर (तीन महीने में तीसरी बार) में कटौती की, रेपो और रिवर्स रेपो दर को फरवरी 2020 में 5.15% और 4.90% से घटाकर क्रमशः 4.0% और 3.35% कर दिया; और वृद्धि फिर से उसी स्थिति में लाने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण रुख बनाए रखा। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने व्यापार में सहायता करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की। इन उपायों में आरबीआई ने 31 जुलाई, 2020 तक किए गए संवितरण के लिए प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण की मौजूदा अवधि को एक साल से बढ़ाकर 15 महीने तक करने की घोषणा की। भारत में 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले किए गए आयातों (सोना/हीरे और कीमती रत्न/आभूषणों के आयात को छोड़कर) के लिए भुगतान की तारीख, शिपमेंट की तारीख से 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने तक कर दी। एक्ज़िम बैंक को 15,000 करोड़ की ऋण-व्यवस्था के जरिए 90 दिनों (एक वर्ष तक के रोलओवर के साथ) लिक्विडिटी सुविधा दी, ताकि बैंक यूएस डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' नामक एक आर्थिक पैकेज की शुरुआत की है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए, यह पैकेज भूमि, श्रम, लिक्विडिटी और कानून संबंधी क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा। 5 दिनों की अवधि में घोषित यह पैकेज, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, जनसांख्यिकी और मांग जैसे पांच स्तंभों की बुनियाद है।

20.97 लाख करोड़ के इस पैकेज में 38.2% हिस्सा भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणाओं से रहा। राजस्व संबंधी पैकेज में लिक्विडिटी सुनिश्चित करने की घोषणा की गई है, विशेष रूप से इसमें एमएसएमई की हिस्सेदारी (आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का 28.4%) अहम है। (तालिका 2)

तालिका 2: आत्मनिर्भर भारत अभियान का विवरण

घोषणा की तारीख	नीति	राशि (लाख करोड़ रुपये)	प्रभाव
26 मार्च-20	राजकोषीय पैकेज की पहली किस्त	1.92	तत्काल प्रभाव, हालांकि, प्रति व्यक्ति / परिवार के लिए दी जाने वाली सहायता राशि मांग बढ़ाने के लिए बहुत कम है।
मार्च/अप्रैल 2020	आरबीआई की नीतिगत घोषणाएं (वास्तविक उपयोग की गई राशि)	8.02	तत्काल प्रभाव, अन्य के साथ-साथ लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट्स को मोरेटोरियम
13 मई-20	राजकोषीय पैकेज की दूसरी किस्त (भाग 1-लिक्विडिटी, मुख्य रूप से एमएसएमई और एनबीएफसी को)	5.95	तालाबंदी हटते ही तत्काल
13 मई-20	भाग 2 – प्रवासी श्रमिकों, किसानों, सड़क पर सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों पर ध्यान केंद्रित करना	3.10	तत्काल ये मध्यम अवधि का प्रभाव
15 मई-20	भाग 3 – कृषि और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देना	1.50	मध्यम से दीर्घावधि प्रभाव
16 मई-20	भाग 4 – आठ प्रमुख क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार	0.08	मध्यम से दीर्घावधि प्रभाव
17 मई-20	भाग 5 – सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधार और सहयोग	0.40	तत्काल से दीर्घावधि प्रभाव, क्योंकि 1 साल तक नए दिवालियापन मामले न होने से तत्काल राहत से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की अनुकूल उद्यम नीति जैसे सुधार लागू होंगे।
	कुल	20.97	

आत्मनिर्भर भारत अभियान से सीधे लाभान्वित होने वाले प्रमुख भारतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: कृषि और संबद्ध गतिविधियां (कृषि प्रसंस्करण, सूक्ष्म खाद्य उद्यम और कृषि-संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, आदि); पशुपालन; हेल्थकेयर और संबंधित बुनियादी ढांचा; निर्माण (अन्य के साथ-साथ संबंधित उद्योग – सीमेंट, लोहा और इस्पात); शिक्षा और संबंधित बुनियादी ढांचा (मुख्य रूप से ई-लर्निंग); शक्ति; खनन; कोयला; खनिज; रक्षा निर्माण; नागर विमानन; अंतरिक्ष; परमाणु ऊर्जा; एमएसएमई; बैंकिंग; और एनबीएफसी, एमएफआई और एचएफसी। ■

भारत का टैरिफ फ्रेमवर्क: प्रमुख समस्याएं और नीतिगत सुझाव

1990 के दशक तक एक बंद अर्थव्यवस्था होने के बाद, भारत ने 1991 में प्रमुख रूप से टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं दोनों को कम करते हुए बड़े पैमाने पर श्रृंखलाबद्ध व्यापार सुधार शुरू किए। इसमें मात्रात्मक प्रतिबंधों को चरणबद्ध किया गया और विदेशी निवेश के लिए सीमाओं को कम किया गया। फिर भी, टैरिफ के मोर्चे पर कई नीतिगत क्षेत्र और मुद्दे हैं जिन्हें अधिक व्यापार उदारीकरण सुनिश्चित कर सुलझाने और टैरिफ संरचना में मौजूदा विसंगतियों को दूर करने आवश्यकता है।

टैरिफ का स्तर

टैरिफ दरों में लगातार कमी के बावजूद, भारत के आयात शुल्क को दुनिया में सबसे अधिक माना जाता है, खासकर अगर कुल शुल्कों को हिसाब में लिया जाए। 2018 में भारत का भारत के सामान्य औसत लागू तरजीही देश (एमएफएन) टैरिफ 17.1% को दुनिया में पांचवां सबसे अधिक और भारत के अन्य व्यापारिक भागीदारों की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा, संरक्षणवादी उपायों के हालिया वैश्विक रुझानों के बाद, 2018 में सामान्य और भारित टैरिफ दोनों बढ़ गए हैं।

हालाँकि, संपूर्ण दरें केवल सामान्य रुझान को समझने में मदद कर सकती हैं। विभिन्न टैरिफ संकेतकों में सापेक्ष रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि आयात पर भारत के टैरिफ उससे काफी कम हैं, जितनी दिखाई देती हैं, और नीति निर्धारण के लिए इसके महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं। अधिमान्य टैरिफों और विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न रियायतों और छूटों के कारण, प्रभावी रूप से लागू टैरिफ और वास्तविक टैरिफ बहुत कम हैं। जबकि भारत के औसत भारित एमएफएन टैरिफ (कुल) में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है। औसत भारित प्रभावी टैरिफ (एएचएस) एमएफएन टैरिफ से कम हैं, जो भारत द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत टैरिफ रियायतों का संकेत है। रियलाइज्ड टैरिफ (कुल) में भी गिरावट आई है, और यह सामान्य औसत एमएफएन टैरिफ और सामान्य औसत प्रभावी टैरिफ दोनों से कम है। वहीं दूसरी ओर, वास्तविक टैरिफ (मूल), 2009-2018 की अवधि के दौरान सबसे कम दर 1.8% से 3.2% तक रहे। स्पष्ट है, भारत में प्रभावी टैरिफ बहुत कम हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि इन तथ्यों को उजागर करते हुए इस गलत धारणा को तोड़ा जाए कि भारत एक उच्च टैरिफ वाला देश है और जहाँ भी संभव हो एमएफएन टैरिफ को प्रभावी टैरिफ स्तरों के आसपास रखा जाए।

उल्लेखनीय है कि भारत के मौजूदा लागू टैरिफ डब्ल्यूटीओ से जुड़े टैरिफ से कम हैं, लेकिन टैरिफ को कम करने की गुंजाइश बनी हुई है। रियलाइज्ड टैरिफ और एमएफएन लागू टैरिफ के बीच की खाई को पाटने के लिए टैरिफ के सावधानीपूर्वक युक्तिसंगत बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले 10% से ऊपर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) के साथ टैरिफ लाइनों को युक्तिसंकगत बनाया जा सकता है। यहां तक कि गैर-कृषि क्षेत्र में 10% की दर वाली वस्तुओं को युक्तिसंगत बनाने पर विचार किया जा सकता है।

टैरिफ युक्तिकरण के मामले में एक और मुद्दा कुल शुल्कों की संख्या के स्तर का है। भारत के कुल आयात शुल्क जिसमें बीसीडी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) और समाज कल्याण अधिभार (SWS) शामिल हैं, गैर-कृषि वस्तुओं में से अधिकांश में BCD से लगभग दोगुने हैं। समाज कल्याण अधिभार के लिए कोई रिफंड या इनपुट क्रेडिट नहीं है, और आईजीएसटी के मामले में, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपलब्ध होने पर पहले आईजीएसटी का भुगतान करना होता है, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना होता है। कुछ अंतिम उपभोग के सामानों के अलावा, आईटीसी का दावा करने में समस्याएं आती हैं। इसलिए, कुल शुल्कों के स्तर को कम करने के लिए आईजीएसटी को थोड़ा आसान बनाने और आयातों से समाज कल्याण अधिभार को हटाने की ज़रूरत है। यह भारत को व्यापार वार्ताओं में अतिरिक्त माइलेज भी दे सकता है। चरणबद्ध तरीके से टैरिफ को कम करने से निर्यातों में मदद मिल सकती है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक एकीकरण हो सकता है। टैरिफ में कमी के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि क्षेत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्यों और इन संवेदनशील वस्तुओं में हितों के अनुरूप यथासंभव एक्सक्लूज़न लिस्ट में रखना चाहिए।

इनवर्टेड शुल्क ढांचा

हालांकि भारत सरकार समय-समय पर इन्वर्टेड शुल्क ढांचे के विषय में उपाय करती रही है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में इन्वर्टेड शुल्क के उदाहरण मिलते हैं, और नए भी उभर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के कारण एक नए प्रकार का इन्वर्टेड शुल्क भी सामने आया है, जिसमें अधिमान्य शुल्कों के तहत तैयार माल का आयात टैरिफ शून्य/कम है, जबकि कच्चे माल और मध्यवर्ती माल जैसे उत्पादन के शुरुआती चरणों में नॉन प्रेफेरेंशियल टैरिफ के कारण माल के आयात पर टैरिफ अधिक होता है। इनवर्टेड शुल्क संबंधी इस तरह के अन्य विशिष्ट मामलों से निपटने की आवश्यकता है।

नॉन-एड वैलोरेम (एनएवी) टैरिफ

गैर-कृषि क्षेत्र में भारत के नॉन-एड वैलोरेम (एनएवी) टैरिफ में पिछले कुछ सालों में गिरावट आई है, तथापि 2018 में लागू एमएफएन टैरिफ लाइनों के 5.5% नॉन-एड वैलोरेम रहे। यहां तक कि 2017 में आयातों में इन टैरिफ लाइनों का हिस्सा भारत के कुल आयातों का केवल 0.3% रहा।

टेक्सटाइल क्षेत्र में कई एनएवी टैरिफ हैं। हालांकि, कृषि क्षेत्र में टैरिफ लाइनों की दृष्टि से (2018 में 0.3%) में एनएवी टैरिफ गैर-कृषि क्षेत्र की तुलना में कम हैं, तथापि आयात की हिस्सेदारी के मामले में, 2017 में इसकी 2.9% की उच्चतर हिस्सेदारी थी। हालांकि कुछ विकसित देशों में भी नॉन-एड वैलोरेम टैरिफ के साथ कई टैरिफ लाइनें हैं। टैरिफ ढांचे को सरल बनाने के लिए बेहतर होगा कि भारत एनएवी टैरिफ के साथ टैरिफ लाइनों को अधिकतम संभव सीमा तक कम कर दे। इसके अलावा, अल्पावधि में विशिष्ट शुल्क भी संभव सीमा तक एड वैलोरेम शुल्कों में परिवर्तित किए जा सकते हैं।

विभिन्न टैरिफ दरें

टैरिफों के संबंध में एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दा भारत में मूलभूत सीमा शुल्क की कई दरें हैं। हालांकि टैरिफ सुधारों से भारत के चरम शुल्क को कम करने में मदद की है। फिर भी 2019 तक, शून्य शुल्क दरों सहित 11,839 टैरिफ लाइनों को कवर करते हुए अभी भी 24 एड वैलोरेम टैरिफ दरें हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में टैरिफ दरों की संख्या कम हो गई है, तथापि यदि केवल एड वैलोरेम टैरिफ दरों को ही लिया जाए तो भी ये अधिक हैं। अगर एनएवी पर भी विचार किया जाए तो 2018 तक भारत में लगभग 252 अलग-अलग एमएफएन शुल्क दरें हैं। इसके अलावा, यदि भविष्य में नॉन एड वैलोरेम टैरिफ दरों को एड वैलोरेम टैरिफ में बदल दिया जाता है, तो इन दरों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। अतः टैरिफ दरों की संख्या को कम करने की बहुत आवश्यकता है। टेल एंड (ऊपरी और निचली सीमा) पर कुछ टैरिफ दरों का विलय करने से टैरिफ लाइनों को प्रभावित किए बिना एक बार में कई टैरिफ दरों की संख्या को आसानी से कम किया जा सकता है।

अधिमानी टैरिफ से संबंधित समस्याएं

हालांकि भारत मुक्त व्यापार समझौतों के क्षेत्र में देर से प्रवेश करने वाला देश है, लेकिन भारत ने कई अधिमानी व्यापार समझौते (पीटीए) किए हैं। इनमें क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए), मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) शामिल हैं। 2016-2018 के दौरान, भारत के कुल आयातों में सभी एफटीए से अधिमानी आयातों की हिस्सेदारी 16%-17% के बीच रही। एफटीए/आरटीए भागीदारों से भारत द्वारा आयात में अधिमानी आयात का हिस्सा विशेष रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), जापान और चिली के मामले में काफी अधिक है। हालांकि, भारत से उनके आयात में इन एफटीए/आरटीए भागीदारों के अधिमानी आयातों की हिस्सेदारी बहुत कम है। उदाहरण के लिए, भारत से सिंगापुर के कुल आयात में अधिमानी आयातों की हिस्सेदारी नगण्य है, क्योंकि सिंगापुर के एमएफएन टैरिफ पहले ही कम थे। विश्लेषण से पता चलता है कि एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (एप्टा) को छोड़कर अन्य सभी एफटीए साझेदार देशों से भारत के आयात पर अधिमानी टैरिफ (भारित) एमएफएन टैरिफ से काफी कम है। जबकि भारत के एफटीए भागीदारों की ओर, दक्षिण कोरिया, एप्टा और मर्कोसुर को छोड़कर अधिमानी टैरिफ सभी मामलों में एमएफएन टैरिफ के अधिक निकट हैं। इससे पता चलता है कि भारत द्वारा अपने एफटीए भागीदारों को दी गई वरीयता का मार्जिन मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया और एप्टा के मामले में भारत को दिए गए वरीयता के मार्जिन से अधिक है। इस प्रकार, टैरिफ के संदर्भ में भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में कुछ 'असमान विनिमय' है।

एक और उल्लेखनीय मुद्दा भारत से एफटीए भागीदारों के आयात में अधिमानी व्यापार के तहत वस्तुओं की कम कवरेज और भारत को दिया गया अपेक्षाकृत कम वरीयता मार्जिन है। यह समस्या भारत द्वारा एफटीए की कम उपयोग दर से बढ़ रही है। तदनुसार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ मामलों को छोड़कर, टैरिफ के मामले में एफटीए से लाभ भारत के लिए सीमित रहे हैं।

जबकि एफटीए/आरटीए में टैरिफ के अलावा अन्य कारक भी महत्त्वपूर्ण हैं। टैरिफ के महत्त्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, खासकर एक शून्य बजटिंग प्रयोग के अनुरूप मौजूदा एफटीए/आरटीए के समुचित मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से मौजूदा एफटीए/आरटीए के राजस्व प्रभाव के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा, भारत को कोई भी नए एफटीए/आरटीए करने से पहले सावधान रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यूएसए द्वारा भारत से जीएसपी लाभ को वापस लेने के साथ, भारत के अन्य एफटीए/आरटीए भागीदारों से यूएसए बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। इस संदर्भ में, भारत को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या एलडीसी को दी गई मौजूदा रियायतों में से किसी का भी पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा, विकासशील देश एफटीए भागीदारों के लिए ग्रैजुएशन क्लॉज के साथ, भारत को एफटीए भागीदारों के लिए कुछ रियायतें देने के लिए 'सनसेट क्लॉज' को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए, भारत के एफटीए के संदर्भ में टैरिफ संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है। ■

दोराहे पर भारतीय मोटर वाहन उद्योग

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में सुविकसित परिवहन प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस मामले में भारत भी अपवाद नहीं है। वर्ष 2018 में, इस क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.1% और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जीडीपी का 49% रहा। भारत में, इस क्षेत्र को लंबे समय से उभरते क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और खासकर कारों और दुपहिया वाहनों के लिए यह दशकों से दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।

यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह क्षेत्र किसी भी देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के संचालक के रूप में केंद्र में रहता है क्योंकि यह अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेज को मजबूत करता है। ऑटो सेक्टर द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न सेक्टोरल लिंकेज इसलिए भी महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये ऑटो क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए विभिन्न असमान क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए पर्याप्त होते हैं।

आईएमएफ के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2019 के अनुसार, 2018 में जीडीपी में मंदी का लगभग 20% और वैश्विक व्यापार में मंदी का लगभग 30% योगदान ऑटो सेक्टर के कारण ही रहा। 2018 में 3.5% का एएजीआर दर्ज करते हुए वैश्विक ऑटोमोबाइल की बिक्री 95.1 मिलियन यूनिट दर्ज की गई, जो 2008 में 68.3 मिलियन यूनिट थी। हालांकि, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से 2018 में पहली बार इस क्षेत्र में गिरावट देखी गई। 2018 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई (2017 के मुकाबले 0.6% गिरावट), इससे पहले 2009 में गिरावट (2008 के मुकाबले 4% गिरावट) दर्ज की गई थी।

वर्ष 2000 के बाद से, भारत में मोटर वाहन उत्पादन (दो और तीन पहिया वाहनों को छोड़कर) एक साल में 8 लाख यूनिट से बढ़कर 5 मिलियन यूनिट हो गया है। दो और तीन पहिया वाहनों को मिलाकर, यह आंकड़ा 4.76 मिलियन यूनिट से बढ़कर 31 मिलियन हो जाता है। पिछले कुछ दशकों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने वाले तीन प्रमुख कारक रहे– बढ़ती आय, वाहन ऋणों की उपलब्धता, और उद्योगों में एफडीआई को खोलना। सब–सेगमेंट के संबंध में, दुपहिया वाहनों का पर्याप्त विकास हुआ और 2019 में यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया। वाणिज्यिक वाहनों का विकास काफी हद तक अर्थव्यवस्था में बढ़ती बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों से प्रेरित था।

जहां तक भारत में ऑटो सेक्टर में निवेश के की बात है तो 2000–2019 के दौरान एफडीआई इक्विटी आवक कुल 23.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। यह सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी आवक प्राप्त करने वाले अर्थव्यवस्था के शीर्ष पांच क्षेत्रों में से एक रहा। वर्ष 2018–19 के लिए, इस क्षेत्र में कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2.6 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग में 80 के दशक की शुरुआत से ही अभूतपूर्व विकास हुआ है। भारत में निर्मित पहली कारों के साथ हिंदुस्तान एंबैसडर, स्टैंडर्ड, प्रीमियर और मारुति 800 को बढ़ते मध्य वर्ग से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनियों के विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत, एशिया में एक पसंदीदा स्थान बन गया है।

ऑटोमोबाइल्स के विनिर्माण के लिए खुद को प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के अलावा, भारत यात्री और वाणिज्यिक वाहनों, दोनों के लिए ऑटो निर्यात हब के रूप में उभरा है। विश्व की बड़ी कंपनियों के लिए भारत में किफायती विनिर्माण उपलब्ध है और वे अपने निर्यातों के लिए भारत को विनिर्माण आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि, वर्तमान में यह क्षेत्र एक ऐसे मोड़ पर है, जहां विपरीत परिस्थितियां सामने हैं और इसकी दिशा निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जबकि चल रही मंदी का एक हिस्सा अर्थव्यवस्था में गिरावट की कुल मांग के साथ जुड़ा है और एक हिस्सा ऑटो सेक्टर में हुए अपरिहार्य संरचनात्मक परिवर्तनों से भी जुड़ा है।

साझा गतिशीलता (शेयर्ड मोबिलिटी) के विकास को चैनलाइज़ करना

- अग्रणी कार विनिर्माता पूरी तरह से व्यक्तिगत ऑटोमोबाइल की बिक्री पर आश्रित नहीं कर सकते और उन्हें निर्वहन के लिए अपने व्यापार मॉडल को नयापन देना होगा और उसमें सुधार लाना होगा।

व्यापार करार

- एफटीए में प्रवेश करते हुए ऐसे स्थानों पर कुछ विशेष वाहनों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है, जो विशेष रूप से क्षेत्रीय या वैश्विक आपूर्ति के अनुकूल हैं।

एफडीआई में सुधार लानाः खामियों को दूर करना करना

- नई कंपनियों के आने, तकनीक–उन्नयन और सुरक्षा के उच्च मानकों के पालन के साथ–साथ कस्टमाइजेशन के लिए बढ़ती जरूरतों के चलते भारतीय ऑटो उद्योग के भविष्य के लिए एफडीआई एक आवश्यक कारक बन गया है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति मजबूत करना

- बांग्लादेश, नाइजीरिया और श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्थाओं में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की मांग में तेजी से होने वाली वृद्धि ऐसे बढ़ते बाजारों में न केवल भारत की मूलभूत क्षमता को प्रदर्शित करती है, बल्कि इस वृद्धि को निरंतर बनाए रखने के द्वार भी खोलती है, क्योंकि इस क्षेत्र में घरेलू बाजारों में मांगस्थिर है।

अफ्रीका में पुरानी कारों के बाजार पैठ बढ़ाना

- भारत से अफ्रीका को जाने वाली सस्ती हैचबैक कारों का निर्यात दोनों क्षेत्रों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी हो सकता है।

विद्युत वाहनों (ईवी) को अपनाना

- इसके अलावा, बैटरियों का घरेलू स्तर पर विनिर्माण और चार्जिंग सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर भारतीय ईवी बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।

आरसीए अंतर्दृष्टि: फोकस क्षेत्रों को चिह्नित करना

- जर्मनी, मेक्सिको, जापान और अमेरिका की तुलना में भारत को मूल्य के हिसाब से, वैश्विक स्तर पर शीर्ष दस निर्यात वस्तुओं में, से केवल तीन उत्पाद उप–समूहों में आरसीए प्राप्त है।

जीसीसी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध: व्यापार, प्रवासन और प्रेषण

खाड़ी सहयोग परिषद, 6 अरबी देशों का क्षेत्रीय अंतर-सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। इनकी आबादी लगभग 56.8 मिलियन है। 2018 में इनकी अर्थव्यवस्थाओं ने 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया को तेल का बड़ा हिस्सा निर्यात किया, जो वैश्विक जीडीपी का 1.9% रहा। 2009 में यह निर्यात केवल 957.8 बिलियन यूएस डॉलर का था।

जीसीसी के साथ भारत के व्यापार संबंध

पिछले कुछ वर्षों में, जीसीसी भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। भारत और जीसीसी क्षेत्र के बीच कुल व्यापार 2009 के 80.8 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2018 में 118.2 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। 2009-2018 के दौरान, भारत ने इस क्षेत्र से लगातार तेल का आयात किया, जिसके चलते व्यापार घाटा बना रहा। 2018 में, पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यापार में लगभग 15% की वृद्धि हुई, जिसमें इस अवधि के दौरान निर्यात में 1.6% की कमी हुई और आयात में 25.7% की वृद्धि हुई **(चार्ट 2)**।

चित्र 2: जीसीसी देशों के साथ भारत का व्यापार (2009-2018)

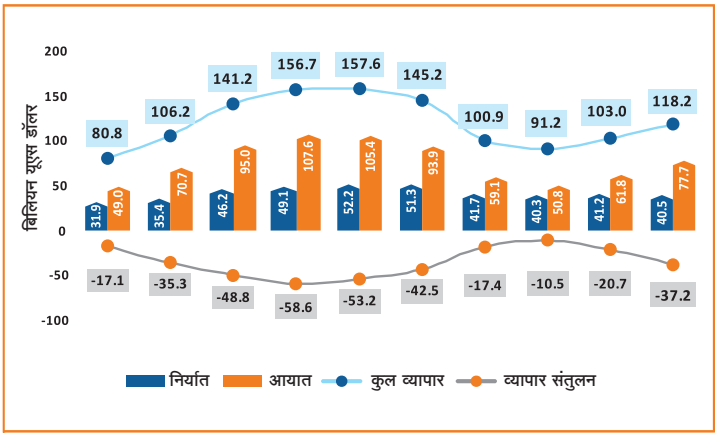

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप, यूएन कॉमट्रेड और एक्जिम बैंक विश्लेषण

निर्यात

जीसीसी क्षेत्र में भारत का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात पर अत्यधिक केंद्रित है। 2018 में जीसीसी क्षेत्र को कुल निर्यात का 70% से अधिक यूएई को ही रहा, जो 29 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसके बाद सऊदी अरब (13.6%), ओमान (5.6%), कतर (4.2%), कुवैत (3.3%), और बहरीन (1.8%) का स्थान रहा।

उत्पादों के मामले में जीसीसी क्षेत्र को भारत के निर्यातों में मोती, कीमती जवाहरात और धातु और खनिज ईंधन एवं उत्पादों का प्रभुत्व रहा। 2018 में, मोती और कीमती जवाहरात की हिस्सेदारी जीसीसी को भारत के कुल निर्यातों का 24.7% थी। इसके बाद खनिज ईंधन और उत्पादों का हिस्सा 19.6% रहा। निर्यात की अन्य वस्तुओं में अनाज (जीसीसी को भारत के कुल निर्यात का 5%), विद्युत मशीनरी और उपकरण (4.9%), जहाज, नौकाएं और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर (4.4%) तथा मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (3.6%) शामिल रहे।

आयात

2018 में जीसीसी से सऊदी अरब और यूएई, भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत रहे। जीसीसी क्षेत्र से भारत के कुल आयात का 70% से अधिक हिस्सा इन्हीं दोनों का था। सऊदी अरब से भारत द्वारा कुल 36.5% का आयात किया गया, जिसका मूल्य 28.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (34.5%), कतर (13.6%), कुवैत (10.1%), ओमान (4.6%), और बहरीन (0.7) %) का स्थान रहा।

जीसीसी क्षेत्र से भारत का कुल आयात 2009 के 49 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2018 में 78 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। 2018 में जीसीसी क्षेत्र से भारत द्वारा कुल आयात का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा खनिज ईंधन और तेल उत्पादों का रहा। 2018 में भारत द्वारा इस क्षेत्र से आयातित अन्य प्रमुख उत्पादों में मोती, कीमती जवाहरात और धातु (भारत के कुल आयातों का 9.7%), कार्बनिक रसायन (3.4%), प्लास्टिक और इसके आभूषण (2.8%), और उर्वरक (2%) शामिल रहे।

जीसीसी देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के अवसर

व्यापार में वृद्धि काफी हद तक जीसीसी देशों के पक्ष में रही है, क्योंकि जीसीसी से भारतीय आयातों की वृद्धि दर, जीसीसी को भारतीय निर्यातों की वृद्धि दर से अधिक रही। जीसीसी क्षेत्र के साथ भारत का समग्र व्यापार घाटा रहा, क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में तेल का आयात अधिकांश अलग-अलग जीसीसी देशों के साथ किया गया। बहरीन और यूएई को छोड़कर, अन्य सभी जीसीसी देशों के साथ व्यापार में भारत का व्यापार घाटा रहा है। इसलिए जीसीसी देशों को भारत के निर्यात को और विस्तार देने और विविधीकरण करने की आवश्यकता है।

जीसीसी में आयात की मांग और भारत की निर्यात क्षमता के आधार पर, भारत द्वारा जीसीसी क्षेत्र को निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों में निर्यात बढ़ाया

जा सकता है: मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (एचएस कोड 84); विद्युत मशीनरी और उपकरण (एचएस कोड 85); रेलवे या ट्रामवे (एचएस कोड 87) के अलावा अन्य वाहन; दवा उत्पाद (एचएस कोड 30); मोती, कीमती जवाहरात और धातु (एचएस कोड 71); लोहे और इस्पात की वस्तुएं (एचएस कोड 73); और प्लास्टिक और प्लास्टिक की वस्तुएं (एचएस कोड 39)।

प्रवासन और प्रेषण

भारत मूल उत्पादन और पारगमन का एक प्रमुख देश है और विभिन्न देशों से श्रमिक यहां आते हैं। विश्व की कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रम शक्ति में भी भारत का महत्त्वपूर्ण योगदान है। संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग (यूएनडीईएसए) के अनुसार, अकेले जीसीसी क्षेत्र में 9.3 मिलियन भारतीयों के साथ, विदेशों में 30 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी हैं। 1970 के दशक के तेल की कीमतों में उछाल के बाद से, खाड़ी क्षेत्र भारतीय श्रमिकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य रहा है। इस प्रकार, भारत-जीसीसी संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि खाड़ी देशों में भारत की एक बड़ी प्रवासी आबादी है, जो कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रम बल प्रदान करती है और भारत के लिए प्रेषण का एक प्रमुख भी स्रोत है। काफी हद तक जीसीसी देशों में बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं भारत से प्रवासी श्रम बल पर निर्भर हैं, जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद। **(चार्ट 3)** है।

चार्ट 3: जीसीसी देशों के प्रवासन संबंधी रुझान (2000-2019)

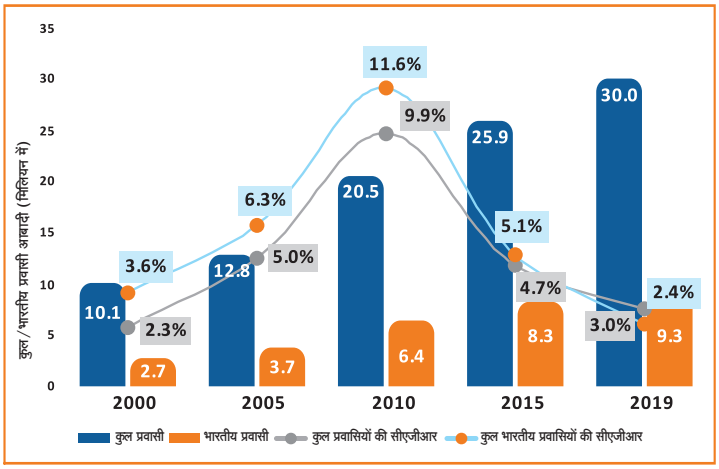

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग (UNDESA)

जीसीसी क्षेत्र में कुल प्रवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय प्रवासियों का है। वर्ष 2000 से जीसीसी की कुल प्रवासी आबादी में भारतीय प्रवासियों का हिस्सा औसतन लगभग 30% रहा है। जीसीसी में भारतीय प्रवासियों की संख्या 2000 की 2.7 मिलियन से बढ़कर 2019 में 9.3 मिलियन हो गई है। 2015 तक, भारतीय प्रवासियों की वृद्धि दर समग्र प्रवासन रुझानों की तुलना में लगातार अधिक रही। लेकिन 2015 के बाद, जीसीसी जाने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या की वृद्धि दर, शेष विश्व से आने वाले कुल प्रवासियों की तुलना में कम हो गई। भारत से प्रवासन की उच्चतम विकास दर 2005-2010 के दौरान देखी गई थी, जिस दौरान जीसीसी पहुंचने वाले वैश्विक प्रवासियों में 9.9% की वृद्धि की तुलना में कुल प्रवासन 11.6% की सीएजीआर से बढ़ा था। वहीं, जीसीसी में, भारतीय प्रवासन में पूर्ववर्ती अवधि की 5.1% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2015-2019 के दौरान केवल 2.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

जीसीसी में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। है और विश्व में सबसे अधिक प्रवासी आबादी भारत से होने के चलते 2018 में जीसीसी क्षेत्र के देश रेमिटैंस के रूप में सबसे अधिक राशि भेजने वाले देशों में से एक रहे, जहां से 116.3 बिलियन यूएस डॉलर की राशि भारत भेजी गई। और भारत 2018 में 78.6 बिलियन यूएस डॉलर के साथ शीर्ष रेमिटैंस प्राप्तकर्ता देश रहा। कुल वैश्विक रेमिटैंस आवक का 11.4% भारत को रहा। भारत को रेमिटैंस 2018 में गत वर्ष के 68.9 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 14% बढ़कर 78.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। बीच में कुछ वर्षों के दौरान मामूली गिरावट को छोड़कर 1990 से भारत को धन-प्रेषण (रेमिटैंस) लगातार बढ़ा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2016-2017 में भारत के आवक धन-प्रेषणों संबंधी अधिकृत डीलरों के चौथे दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के कुल धन-प्रेषण आवक का 53.5% से अधिक अकेले जीसीसी देशों से आया। जीसीसी देशों में, यूएई भारत के लिए सबसे बड़ा रेमिटैंस स्रोत है, जिसका हिस्सा कुल आवक रेमिटैंस का 26.7% है। इसके बाद सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का स्थान आता है।

आगे की राह

भारत और जीसीसी देश एक दूसरे के बीच मौजूदा साझेदारी का पारस्परिक लाभ उठा रहे हैं। तथापि, दीर्घावधि में भारत-जीसीसी संबंधों को और अधिक मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए, भारत-खाड़ी सहयोग के लिए नए कारक और आने वाले समय में अधिकाधिक सहयोग की संभावनाएं तलाशना अनिवार्य है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करने वाली कुछ नीतियां उत्प्रेरक निम्नलिखित हो सकती हैं: (i) भारत से निर्यात संभाव्यता वाली चिह्नित वस्तुओं के आधार पर व्यापार का विस्तार करना, जिससे खाड़ी देशों के साथ भारत के उच्च व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी; (ii) बाजारों का विविधीकरण; (iii) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) बढ़ाना या जीसीसी के साथ आर्थिक साझेदारी के लिए नई संभावनाएं तलाशना; (iv) लोगों की अस्थायी आवाजाही की अनुमति देने के लिए सहयोग; (v) सेवा क्षेत्र में और अधिक सहयोग; (vi) व्यापार लॉजिस्टिक्स में सुधार; (vii) एकीकृत व्यापार प्रतिनिधि निकाय को चिह्नित करना; और (viii) अन्य के साथ-साथ लोगों में आपसी विचार-विमर्श को बढ़ाना। ■

कोविड–19 के दौरान व्यापार अनिश्चितता से निपटना

कोविड–19 महामारी भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि पॉज़िटिव पाए जाने वाले मामलों की संख्या और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का बुनियादी ढांचा हर देश में अलग हो सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए हर देश द्वारा अस्थायी तालाबंदी का समान उपाय अपनाया गया। यह अस्थायी तालाबंदी जो भारत सहित कई देशों में अब भी आंशिक रूप से लागू है।

भारत के लिए हालिया व्यापार रुझान

वर्ष 2018–19 के मुकाबले वर्ष 2019–20 में भारतीय मर्चेंडाइज़ निर्यात और आयात दोनों में क्रमशः 5% और 8.1% की गिरावट दर्ज की गई। यद्यपि, 2019–20 के कुछ चुनिंदा महीनों के दौरान भारतीय निर्यात और आयात में कुछ ऋणात्मक विकास दर (वर्ष–दर–वर्ष) दर्ज की गई थी, पर मार्च 2020 के महीने में उच्च ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2019 के मुकाबले मार्च 2020 में निर्यात और आयात में क्रमशः 35% और 29% तक की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल 2020 में यह गिरावट और भी अधिक रही। स्पष्ट है कि कोविड–19 को रोकने के उपाय करने में, दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ भारतीय व्यापार में भी रुकावट आई है।

चार्ट 4: भारतीय निर्यातों और आयातों में वृद्धि: हालिया मासिक रुझान

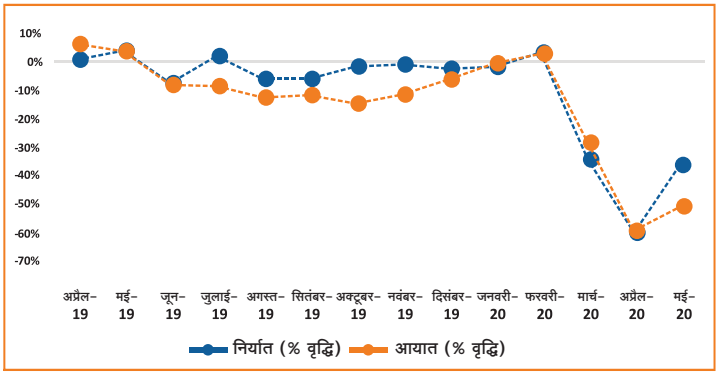

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; एक्ज़िम बैंक शोध

कोविड–19 के कारण व्यापार चुनौतियों से पार पाने की रणनीतियां

हालांकि भारत में कोविड–19 अपनी चरम सीमा से कम रहने की उम्मीद है, तथापि भारत सरकार ने महामारी के कम होते ही आर्थिक गतिविधियां और व्यापार को दोबारा शुरू करने के उपाय शुरू कर दिए हैं।

राजकोषीय मार्ग का उपयोग करना: राजकोषीय घाटे को कम करना

भारतीय अर्थव्यवस्था को मांग और आपूर्ति दोनों मोर्चों पर झटके लगने का अंदेशा है। आपूर्ति के मोर्चे पर, भारत मूल्य श्रृंखलाओं के संबंध में विभिन्न देशों पर निर्भर है और इस समय उन देशों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मांग की बात करें तो, प्रमुख रूप से उपभोक्ताओं की ज़रूरतों, फैशन उन्मुख उत्पादों और लक्ज़री वस्तुओं की मांग में गिरावट रहने का अनुमान है। सरकार अपने खर्च में कटौती करते हुए, इस राशि को स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक सुधारों के प्रबंधन में लगा सकती है। एमपीलैड फंड को निलंबित करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन प्राप्तकर्ताओं के महंगाई भत्ते को फ्रीज करने की घोषणाएं कर दी गई हैं। विधायकों ने भी अपने वेतन और भत्तों में कटौती करने के लिए सहमति दे दी है।

वहीं, सरकार भी अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संशोधित कर सकती है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 21 के लिए 3.5% निर्धारित किया गया था। वस्तुतः, भारत सरकार ने राजकोषीय उपाय करना पहले ही शुरू कर दिया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को सहायता

भारत के निर्यात में एक बड़ा हिस्सा एमएसएमई क्षेत्र का है। इसलिए ये किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौद्रिक नीति की दृष्टि से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आरबीआई ने हाल ही में 50,000 करोड़ के टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (एलटीआरओ) की घोषणा की है, जिसमें गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं सहित छोटे और मध्यम कॉर्पोरेट्स को पर्याप्त लिक्विडिटी मिल सकेगी।

एक व्यापक पैकेज ऐसा जरिया हो सकता है जिससे वेतन, वैधानिक दायित्वों, किराये और अन्य उपयोगिताओं के भुगतान में राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार आगे के नुकसान को कवर करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण, और निर्यात लाभों को बढ़ाने की चिंताओं को दूर करने पर विचार कर सकती है।

भारत आने वाली कंपनियों को परिवेश प्रदान करना

चीन, लंबे समय से वैश्विक मूल्य श्रृंखला का केंद्र रहा है। चीन में काफी बड़ी संख्या में कंपनियों के उत्पादन और असेंबली केंद्र हैं। तथापि, चीन पर निर्भरता वैश्विक निर्माताओं के लिए लाभकारी साबित नहीं हुई है। नतीजतन, कई कंपनियां अपने संयंत्रों को स्थापित करने के लिए नए गंतव्यों की तलाश कर रही हैं, और भारत समुचित उपायों के साथ इस अवसर को भुना सकता है।

नीतिगत के स्तर पर, भारत को अपनी खामियों को दूर करने पर काम करना चाहिए और वैश्विक निवेशकों के लिए ऐसा परिवेश बनाना चाहिए, जिसमें भारत एक सफल वैकल्पिक गंतव्य के रूप में उभर सके। बुनियादी ढांचागत दक्षता, विशेष रूप से बिजली की आपूर्ति, बेहतरीन बंदरगाह और सड़क संचालन में सुधार कर भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बनाया जा सकता है। भारत को मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए जहां वह दूसरों के इनपुट्स पर निर्भर रहने की जगह पुर्जों और घटकों का निर्माण कर सकता है, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में, और आपूर्ति श्रृंखला का एक हिस्सा बन सकता है। इससे न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे, बल्कि भारत के लिए निर्यात–संचालित विकास के लिए एक कुशल मॉडल भी बन सकता है। ■

एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण–व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण–व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 61 देशों को 25.70 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 261 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण–व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

एक्ज़िम बैंक ने अप्रैल–जून 2020 के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित ऋण–व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए:

मलावी सरकार को पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए 215.68 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की है। उपरोक्त ऋण–व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ, एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 395.68 मिलियन यूएस डॉलर की कुल 5 (पाँच) ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेशिंग संयंत्र, कपास प्रसंस्करण सुविधाओं, ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव, चीनी प्रसंस्करण उपकरण, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए और लिखुबुला नदी से मुलांजे से ब्लैंटायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

निकारागुआ सरकार को एल्डो शैवेरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के वित्तपोषण के लिए 20.10 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की गई। इस एलओसी करार पर हस्ताक्षर के साथ, एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से निकारागुआ सरकार को अब तक 87.63 मिलियन यूएस डॉलर की कुल 4 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं निकारागुआ सरकार को दो सबस्टेशनों के निर्माण के लिए उपकरणों की आपूर्ति, ट्रांसमिशन लाइनों और नए सबस्टेशन के निर्माण, मौजूदा सबस्टेशनों के विस्तार और एक अस्पताल के पुनर्निर्माण संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

सुदत्त मंडल
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
ऑफिस ब्लॉक, टावर–1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली – 110023.
फोन: (011) 24607700,
ई–मेल: eximloc@eximbankindia.in

सफलता की कहानियाँ

दास्तान–ए–कामयाबी: श्रीलंका सरकार को प्रदत्त ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आपूर्ति

श्रीलंका सरकार को प्रदान की गई 382.37 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत वित्तपोषित एक परियोजन में राइट्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में श्रीलंकाई रेलवे को डीजटल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आपूर्ति की। ये लोकोमोटिव ईंधन की कम खपत करते हैं और इनसे श्रीलंका के लोगों को किफायती दामों पर जन परिवहन के साधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ■

तिमाही गतिविधियां

सुश्री हर्षा बंगारी एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक नियुक्त

सुश्री हर्षा बंगारी को भारतीय निर्यात–आयात बैंक की उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले सुश्री बंगारी बैंक की मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने 1995 में एक्ज़िम बैंक जॉइन किया था और वर्तमान में वह बैंक के ट्रेजरी एवं लेखा समूह की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। सुश्री बंगारी अनुभवी फायनैंस प्रोफेशनल हैं। उन्हें वित्तीय क्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्हें बैंक की सभी प्रक्रियाओं और व्यवसाय नीतियों की विशद जानकारी है। उन्हें ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा संसाधनों से लेकर जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा, देयता प्रबंधन जैसे बैंक के समस्त क्रियाकलापों का अनुभव है। अंतरराष्ट्रीय डेट कैपिटल मार्केट तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त उनकी रुचि के क्षेत्रों में शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 50% से अधिक बढ़ा इंडिया एक्ज़िम बैंक का कर पश्चात लाभ

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना और उप प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी ने गुरुवार, 25 जून, 2020 को वर्चुअल प्रेस वार्ता में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा की।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित अनुसार रहीं:

वित्तीय वर्ष 2019–20 के वित्तीय परिणाम

विवरण	वित्त 2019–20 (करोड़ ₹ में)	गत वर्ष से परिवर्तन (%)
ऋण पोर्टफोलियो	99,446	▲ 6.23
गैर–निधिक पोर्टफोलियो	15,869	▲ 12.59
नेट वर्थ	16,285	▲ 11.00
कर पश्चात लाभ	124	▲ 51.00
भारत सरकार को अंतरित शेष लाभ	12.39	▲ 51.00
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	621	▲ 8.76
प्रावधान कवरेज अनुपात	89 %	▲ 400 बीपीएस
जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात	20.13 %	▲ 106 बीपीएस
निवल अनर्जक आस्तियां	1.77 %	▼ 67 बीपीएस

ऋण–व्यवस्थाएं: वर्ष के दौरान बैंक द्वारा भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात में सहयोग के लिए 3.40 बिलियन यूएस डॉलर की 27 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। भारत सरकार की ओर से दी गई इन 259 ऋण–व्यवस्थाओं के पोर्टफोलियो के अंतर्गत 25.46 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धताएं हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं अपनी बढ़ती पहुंच के साथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में 64 देशों में आर्थिक विकास में तेजी लाने में मददगार रही हैं।

परियोजना निर्यात: वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बैंक ने अपनी वाणिज्यिक ऋण योजना के अंतर्गत कुल 2.81 बिलियन यूएस डॉलर के 38 परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों को सहायता दी। बैंक द्वारा इस वित्तीय सहायता प्राप्त कुछ प्रमुख परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों में निम्नलिखित शामिल रहे: बांग्लादेश में रोडवेज़ परियोजना; नाइजीरिया में रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स परियोजना; निकारागुआ और टोगो में विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाएं; अल्जीरिया में साउथ वेस्ट गैस फील्ड विकास परियोजना; म्यांमार में यांगून बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल का विकास; चिली में 190 मेगावाट का सौर डीसी फोटोवोल्टिक संयंत्र; सूरीनाम में पंपों का इंस्टॉलेशन और उनकी कमीशनिंग।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी–एनईआईए): मंजूर सुविधाओं के अंतर्गत वर्ष के दौरान 331.58 मिलियन यूएस डॉलर के संवितरण किए गए और यथा 31 मार्च, 2020 को बीसी–एनईआईए पोर्टफोलियो 1.35 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में निमनलिखित शामिल रहीं: श्रीलंका में जल शोधन परियोजना; मोज़ाम्बिक में बेरा पोर्ट पर एलपीजी स्टोरेज सुविधा; कोत दिफवार, सेनेगल और तंज़ानिया को वाहनों की आपूर्ति; कैमरून, मॉरिटानिया, सेनेगल, ज़ाम्बिया और केन्या में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं; घाना में रेलवे लाइन परियोजना; सूरीनाम में सिंचाई परियोजना; यूगांडा और कैमरून में जल आपूर्ति परियोजना; और मालदीव, ज़ाम्बिया तथा घाना में अन्य परियोजनाएं। बैंक ने कई प्रमुख भारतीय निर्यातकों की ओर से निष्पादित की जाने वाली 28 परियोजनाओं को 3.53 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करने हेतु सिद्धांततः सहमति भी दी है।

विदेशी निवेश वित्त: वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 16 कंपनियों को 8 देशों में उनके विदेशी निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल 2,837 करोड़ की निधिक तथा गैर–निधिक सहायता मंजूर की गई। वर्ष के दौरान सहायता प्रदान किए गए विदेशी निवेशों में निम्नलिखित शामिल रहे: ऑटो पुर्जों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए मोरक्को में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना; चीन में ओलिओरेज़िन विनिर्माण संयंत्र के लिए कार्यशील पूंजी; इंटरमीडिएट कंटेनर बोतल और ड्रमों के विनिर्माण के लिए अमेरिका में ईकाइयों की स्थापना; ओमान सल्तनत में स्थानीय विद्युत उत्पादन के साथ कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक विनिर्माण परियोजना की स्थापना। ■

चुनिंदा देशों का आर्थिक परिदृश्य

मेक्सिको

कोविड-19 महामारी के चलते निजी खपत और निवेश में तेजी से गिरावट के चलते तथा सरकारी खपत में मामूली बढ़त के बावजूद मेक्सिको का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2020 में 9.2% तक गिरावट की आशंका है। यह मेक्सिको के लिए बड़ा आर्थिक झटका होगा, क्योंकि 2019 में इस देश की अर्थव्यवस्था पहले ही 0.3% गिर चुकी है। वित्तीय बाजारों में मेक्सिको वैश्विक विक्रय और फरवरी 2020 से गिरते तेल के दामों के चलते बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्थानीय सरकारी बॉन्ड बाजारों को लगभग 13.4 मिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 1.3%) अनिवासी जावक का सामना करना पड़ा और 28 अप्रैल, 2020 को 10 वर्षीय डॉलर ऋण स्प्रैड 132 बीपीएस से बढ़कर 424 बीपीएस हो गया, लेकिन तब से 269 बीपीएस की गिरावट आई। अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के दुष्प्रभाव की चिंताओं के बीच वर्ष की शुरुआत से अब तक मेक्सिको की मुद्रा पेसो में 18% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। यथा 16 जून, 2020 को विनिमय दर Ps22.34:US$1 रही। तथापि, इस वर्ष विनिमय दर के प्रभावित होने की सीमित संभावना है, क्योंकि कमजोर उपभोक्ता मांग और तेल के न्यून दामों के चलते 2020 के अंत तक मुद्रास्फीति के 2019 की 2.8% की तुलना में गिरकर 2.6% रहने की संभावना है। महामारी के चलते निर्यात राजस्व में कमी आने और पर्यटकों की संख्या कम होने तथा रेमिटैंस गिरने से चालू खाता घाटा 2019 में जीडीपी के 0.2% से बढ़कर 2020 के अंत तक जीडीपी का 2.7% हो जाने का अनुमान है।

श्रीलंका

दुनियाभर में फैली कोविड-19 महामारी के चलते श्रीलंका का वास्तविक जीडीपी 2020 में 1.6% गिरने के आसार हैं। तालाबंदी के कारण रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली फैक्टरियां बंद रहीं, जिनका श्रीलंका से सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। साथ ही पर्यटन क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। बेरोजगारी बढ़ने से निजी खपत में भी गिरावट आएगी। श्रीलंका रुपया हाल के महीनों में लगातार गिरता रहा है और 2020 के अंत तक यूएस डॉलर के मुकाबले 6% गिरकर विनिमय दर SLRs190.2: US$1 रहने के आसार हैं। परिणामतः रुपये में गिरावट आने और खाद्य कीमतों के बढ़ने से 2020 में मुद्रास्फीति दर औसत 4.7% रहने के आसार हैं, जो 2019 में 4.3% थी। 2020 में निर्यातों में कमी आयातों की तुलना में अधिक होने से चालू खाता घाटा 2019 में जीडीपी के 0.5% से बढ़कर 2020 के अंत तक जीडीपी का 1.6% हो जाने का अनुमान है और पर्यटन राजस्व में भी भारी कमी आएगी।

सिंगापुर

वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक चक्र में गिरावट, कमजोर वैश्विक मांग और यूएस तथा चीन के बीच व्यापार तनावों के चलते सिंगापुर के निर्यात उन्मुख उद्योग और व्यापार भी प्रभावित हुए और 2019 में वृद्धि दर महज 0.7% रही। कोरोना वायरस महामारी और उसके साथ तालाबंद के चलते घरेलू और बाहरी मांग में भी भारी गिरावट आने की संभावना है, जिससे सिंगापुर की अर्थव्यवस्था 2020 में 6% तक गिरने की आशंका है। मांग में भारी कमी आने और वैश्विक तेल दामों में गिरावट के चलते परिवहन और सुविधाओं की लागत में कमी आने और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर -0.2% हो जाने की संभावना है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं तथा कमजोर निर्यातों के चलते विनिर्माण और निर्माण भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। निकट भविष्य में पर्यटन-संबंधी सेवाओं में भी कमी आने के आसार हैं, क्योंकि चीन से सिंगापुर आने वाले पर्यटकों की संख्या में आने वाले समय में तेजी से गिरावट आने की आशंका है और सिंगापुर आने वाले कुल पर्यटकों में 20% चीन से ही होते हैं। सिंगापुर डॉलर का मूल्य 2019 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 1.36 था, जिसके 2020 में गिरकर 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 1.45 सिंगापुर डॉलर हो जाने की संभावना है। अप्रैल और मई में फार्मास्यूटिकल निर्यातों में कुछ बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन 2020 में कुल निर्यातों में गिरावट की आशंका है। तथापि, आयात कम करने के चलते 2020 में व्यापार संतुलन में सुधार होगा। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) की नवंबर 2019 में पुष्टि की गई और इससे मिलने वाले लाभों का सिंगापुर के बाहरी क्षेत्र पर 2021 से सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

नाइजीरिया

नाइजीरिया की वृद्धि दर 2019 में स्थिर तेल उत्पादन से मिले सहयोग के चलते 2.2% रही। किन्तु 2020 में 3.4% के आर्थिक संकुचन के साथ मुद्रास्फीतिजनित मंदी की आशंका है। तेल के दामों में हाल में आई गिरावट और कोरोना वायरस फैलने के चलते यह 1983 के बाद सबसे बड़ा आर्थिक झटका होगा। ओपेक+ द्वारा तेल उत्पादन में कटौती करने और मार्च अंतिम सप्ताह से आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तालाबंदी करने से औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है और तालाबंदी के चलते सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। नाइजीरिया की मुद्रा नायरा 2019 में N 306.4: US$ 1 से गिरकर 2020 में N 450.0: US$ 1 पर पहुंच गई। चालू खाता घाटे में ही रहने की संभावना है और 2020 में यह जीडीपी का 3.1% माना जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात में कमी से अधिक गिरावट वर्तमान अवमूल्यन के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण तेल की गिरती कीमतों और निम्नतर रेमिटैंस में आएगी और तेल क्षेत्र में गिरावट के कारण प्राथमिक ऋणों में भी गिरावट आएगी।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

चीनी युआन

¥ ऑफशोर चीनी युआन 27 मई, 2020 को 7.1963 के नौ महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन 23 जून, 2020 को थोड़ा संभलकर 7.0608 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, ऑनशोर युआन 27 मई, 2020 को 7.1766 के आठ माह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था, जो 23 जून, 2020 को 7.0575 पर बंद हुआ।

अर्थशास्त्रियों ने इस तिमाही और 2020 के लिए चीन की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमानों को अपग्रेड किया और आशावादी संकेत दिए कि चीन धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। जून के तीसरे सप्ताह में ब्लूमबर्ग के सर्वे में अर्थशास्त्रियों के अनुसार, देश का सकल घरेलू उत्पाद एक साल पहले की तुलना में 1.5% बढ़ेगा। यह मई के गत सर्वे में दिखाई गई 1.2% की दर से अधिक है। अर्थशास्त्रियों ने पूरे वर्ष के लिए वृद्धि के अनुमानों को भी 1.7% से बढ़ाकर 1.8% कर दिया है।

इस सर्वे के परिणाम बताते हैं कि चीन पर तकनीकी रूप से मंदी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने वर्ष के प्रथम तीन महीनों में कोरोना वायरस के चलते हुई तालाबंदी के परिणामस्वरूप वृद्धि के 6.8% के पूर्वानुमान को तेजी से घटा दिया था।

ब्रिटिश पाउंड

£ पाउंड 23 जून, 2020 को यूरो के मुकाबले तीन माह में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पीएमआई डेटा उम्मीद से अधिक अच्छा रहा, जो मुख्य रूप से वैश्विक जोखिम वहन क्षमता और ब्रेक्ज़िट में परिवर्तन से संचालित है।

आईएचएस मार्किट/सीआईपीएस फ्लैश कंपोज़िट पर्चेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधियों को मापता है। यह पीएमआई डेटा मई के 30.2 से बढ़कर जून में 47.6 हो गया। यह रॉयटर्स पोल से भी अधिक प्रगति दिखाने वाला रिकॉर्ड रहा, जिसमें इसे 41 मापा गया था। हालांकि इसका सब-50 का स्तर अब भी उत्पादन में गिरावट ही दिखाता है।

पिछले तीन महीनों में यूएस डॉलर के मुकाबले 1.2812 के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 23 जून, 2020 को पाउंड 1.2456 के स्तर पर रहा, जो यथा 01 अप्रैल, 2020 को 1.2376 के स्तर पर था। यूरो के मुकाबले स्टर्लिंग में भी गिरावट आई और 23 जून, 2020 को यह 1.1012 के निचले स्तर पर रहा। दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के दोबारा चालू होने से वैश्विक जोखिम वहन क्षमता में परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप पाउंड की रिस्क ऑन, रिस्क ऑफ मुद्रा के रूप में ट्रेडिंग जारी है।

चार साल पहले ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए मतदान किया था। इस वर्ष जनवरी के अंत में इससे बाहर निकलने के बाद, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को अब 2020 के अंत तक नए व्यापार संबंधों पर सहमति बनानी होगी।

जापानी येन

¥ जापानी मुद्रा डॉलर के मुकाबले ¥106 और ¥108 के बीच रही। जापानी येन उसी स्तर के आसपास रहा, जिस स्तर पर यह कोरोना वायरस महामारी के फैलने से पहले था। मार्च मध्य में इसमें मामूली गिरावट आई। लंबे समय से स्थिर यह प्रमुख विनिमय दर अपने आप में बेहद महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। इन रुझानों को देखते हुए बाजार कमजोर येन को अब बीता हुआ कल मान रहे हैं।

डॉलर-येन की जोड़ी को जोखिम वहन क्षमता, भू-राजनीति, व्यापार और निवेश प्रवाहों के लिए वर्षों से हेयर-ट्रिगर के रूप में देखा जाता रहा है। अब इसकी लंबी स्थिरता वैश्विक निवेश दृढ़ता के अभाव को दर्शाती है और यह जितने लंबे समय तक 107 स्तर पर रहेगा, इसकी कल्पना करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा कि यह कैसे टूटेगा। जब 25 मई, 2020 को टोक्यो ट्रेडिंग शुरू हुई, आपातकाल से शहर का बाहर निकलना, उन उत्प्रेरकों में से एक था, जो पहले भी येन में उतार-चढ़ाव के कारक रहे हैं। सुरक्षित मानी जाने वाली इस मुद्रा को हांगकांग में हुए विरोध प्रदर्शनों और हांग सेंग में उत्पन्न हुए अवरोधों; वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनावों; शिंजो आबे के 2012 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी कैबिनेट के लिए न्यूनतम मंजूरी रेटिंग; और यूएस में कोविड-19 के और फैलने जैसे कारकों से और मजबूती मिली।

ब्राजीलियाई रियाल

R$ रॉयटर्स के फॉरेन एक्सचेंज विश्लेषकों के अनुसार, प्रमुख लैटिन अमेरिकी मुद्राओं के यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि यह मजबूती काफी हद तक घरेलू राजनीति में शांति बने रहने और आर्थिक सुधारों पर निर्भर करती है। कोरोना वायरस महामारी के चलते मानव त्रासदी के बावजूद इस क्षेत्र से विश्लेषकों की उम्मीदों पर पानी भी फिर सकता है, क्योंकि इस त्रासदी में पहले से उच्च मृत्यु दर यदि और बढ़ जाती है तो स्थानीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ जाएगी और राजनीतिक द्वंद्व बढ़ेगा तथा आर्थिक नुकसान होगा। जोखिमपूर्ण आस्तियों के वैश्विक बाजार में विक्रय के चलते मार्च में रिकॉर्ड न्यून स्तर पर पहुंचने के बाद अब 2020 के शेष महीनों के दौरान ब्राजीलियाई रियाल में मामूली गिरावट आने का अंदेशा है।

राजनीति ब्राजीलियाई आस्तियों के लगातार पीछे पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टियों की एक अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में राष्ट्रपति को व्यक्तिगत कारणों से कानून प्रवर्तन को अपने हित में इस्तेमाल कराने का आरोप लगाया गया था।

रॉयटर्स पोल के अनुसार, अब से एक वर्ष बाद, रियाल के 5.00 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचने का पूर्वानुमान है। इसमें वर्तमान दर की तुलना में 1.2% की बढ़ोत्तरी होने और मई के मीडियन 12 माह के अनुमानों में 4.0% की गिरावट का पूर्वानुमान है। 2020 में अब तक रियाल में 20.4% की गिरावट आ चुकी है और यह 23 जून, 2020 को डॉलर के मुकाबले 5.1542 के स्तर पर बंद हुआ।

एक्ज़िम मित्र

आईटीसी एचएस कोड सूची अथवा इंडिया हार्मोनाइज्ड को सिस्टम संबंधी सूचना

आईटीसी–एचएस कोड को दो अनुसूचियों में बांटा गया है। आईटीसी (एचएस) आयात अनुसूची I में आयात नीतियों संबंधी नियम और दिशानिर्देश दिए गए हैं, वहीं अनुसूची II में निर्यात नीतियों संबंधी नियम और दिशानिर्देश दिए गए हैं।

आईटीसी–एचएस कोड की अनुसूची I को 21 खंडों में विभाजित किया गया है और फिर हर खंड को अध्यायों में विभाजित किया गया है। अनुसूची I में अध्यायों की कुल संख्या 98 है। इन अध्यायों को सब–हेडिंग में विभाजित किया गया है, जिनके अंतर्गत अलग–अलग एचएस कोड का उल्लेख किया गया है। आईटीसी–एचएस कोड की निर्यात नीति अनुसूची II में 97 अध्याय हैं, जिनमें निर्यात नीतियों से संबंझित दिशानिर्देशों का विवरण दिया गया है।

इसे बेहतर बनाने के लिए जारी प्रक्रिया के रूप में कमोडिटी का विवरण, निष्क्रिय कोड्स को हटाना, नए कोड जोड़ना, उत्पाद के विवरण आदि में परिवर्तन समय–समय पर किए जाते रहे हैं।

भारत सरकार की विभिन्न निर्यात योजनाओं के संबंध में जानकारी

भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न निर्यात योजनाएं:

- अग्रिम प्राधिकार योजना
- कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज और एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक योजना
- जीएसटी में छूट
- शुल्क–रहित आयात प्राधिकार
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं (ईपीसीजी) ज़ीरो ड्यूटी योजना
- पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूट क्रेडिट स्क्रिप योजना
- टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस (टीईई)
- मार्केट एक्सिस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना
- मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) योजना
- मर्चेंडाइज निर्यात संबंधी योजना
- राज्य लेवी में छूट
- निर्यातकों को ढुलाई भाड़ा सहायता

भारत से नारियल के निर्यात की प्रक्रिया संबंधी जानकारी

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने नारियल विकास बोर्ड को नारियल के समस्त उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में अधिसूचित किया है। आप नारियल विकास बोर्ड से निम्नलिखित सेवाओं के संबंध में जानकारियां पा सकते हैं:

- निर्यातकों को रजिस्ट्रेशन–सह–सदस्यता प्रमाणपत्र
- नारियल उत्पादों और नारियल आधारित उत्पादों के निर्यात के लिए भारत से मर्चेंडाइज निर्यात योजना के अंतर्गत लाभ हासिल करना
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सेदारी का सुगमीकरण
- महत्त्वपूर्ण व्यापार सूचना का प्रसार
- निर्यातकों के लाभ के लिए बाजार संभावनाओं और रुझानों का विश्लेषण करना
- निर्यातकों को वाणिज्यिक रूप से महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना और निर्यात बढ़ाने में उनकी सहायता करना
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता और डिजाइन विकास, मानक और स्पेसिफिकेशन, उत्पाद विकास, पैकेजिंग आदि के संबंध में प्रोफेशनल परामर्श
- सेमिनार, सम्मेलन और क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना

साख पत्रों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना

साख पत्र (एलसी) एक निश्चित राशि प्रदान करने के लिए एक सशर्त वचन पत्र होता है, जो आवेदनकर्ता के अनुरोध पर लाभार्थी को विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। साख पत्र के तहत राशि हासिल करने के लिए इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना एक अनिवार्य शर्त होती है। ये दस्तावेज एलसी के नियम एवं शर्तों, लागू यूसीपी 600 के प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पद्धतियों के अनुरूप होने चाहिए। यूसीपी 600 के नियमों में उल्लिखित अनुसार, एक या अधिक मूल परिवहन दस्तावेजों सहित दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण लाभार्थी द्वारा या उनकी ओर से शिपमेंट के 21 दिनों के भीतर किया जाना जरूरी है। ये दस्तावेज प्रस्तुत करने में क्रेडिट समाप्ति तिथि से किसी भी हाल में 21 दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए एक्ज़िम मित्र पोर्टल पर (https://eximmitra.in/en/helpline/letters-credit) (1) एफएक्यू सेक्शन में दस्तावेजों की जांच के लिए मानक देखें।

संपूर्ण टर्नओवर पोस्ट–शिपमेंट गारंटी योजना के संबंध में जानकारी

ईसीजीसी की संपूर्ण टर्नओवर पोस्ट–शिपमेंट गारंटी योजना, निर्यातकों को प्रदान किए गए पोस्ट–शिपमेंट ऋण का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करती है। निर्यात संवर्धन के लिए बैंक संपूर्ण टर्नओवर पोस्ट–शिपमेंट गारंटी योजना को चुनने पर विचार कर लेते हैं। इस योजना की प्रमुख बातें ईसीजीसी की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। (https://www.ecgc.in/english/whole-turnover-packing-credit-wtpc/)

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

मर्चेंडाइज व्यापार

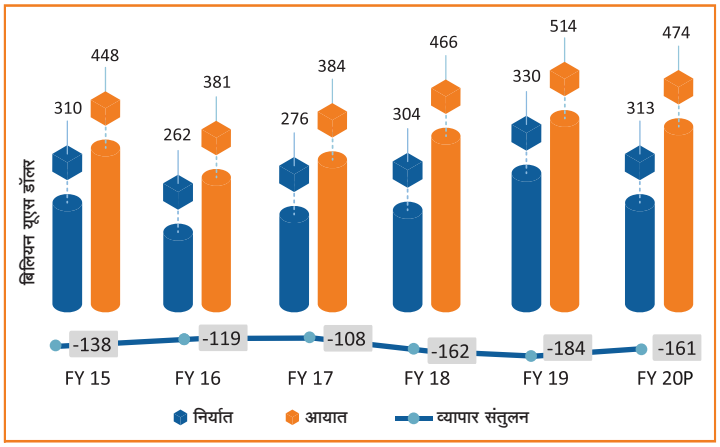

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सेवा व्यापार

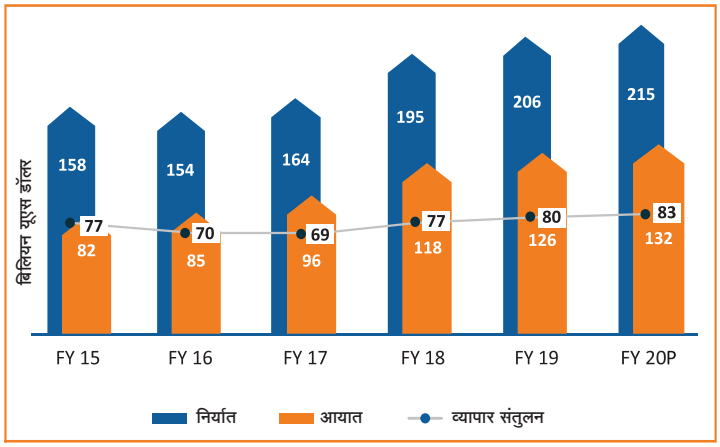

स्रोतः आरबीआई

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह (एफडीआई)

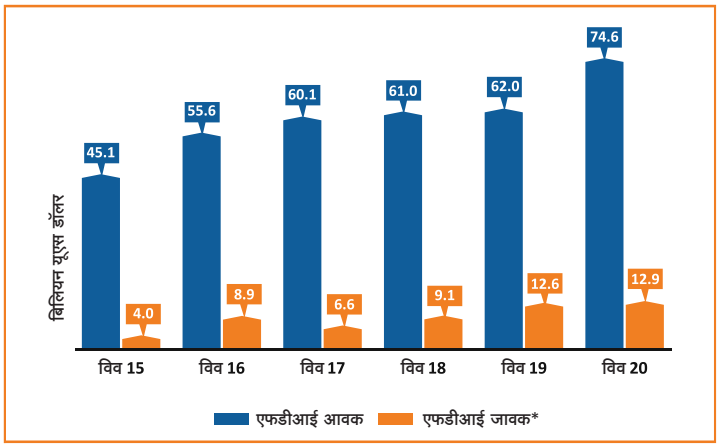

नोटः– एफडीआई जावक में इक्विटी कैपिटल, पुनर्निवेशित आय और प्रत्यावर्तन/ विनिवेश शामिल होता है। इसमें ऋण अथवा जारी की गई गारंटियां शामिल नहीं होती हैं।*

स्रोतः आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

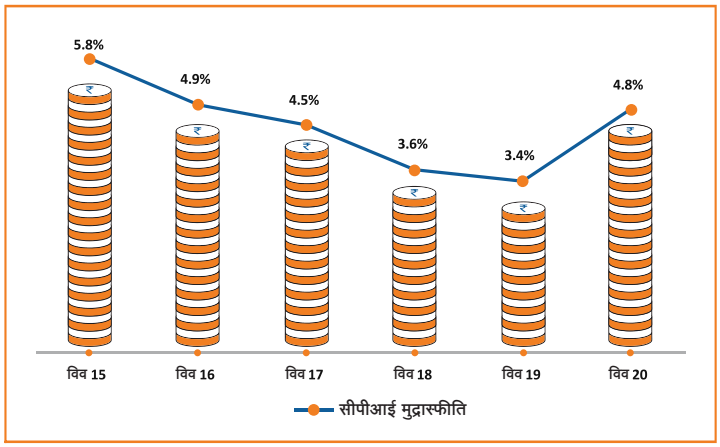

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चालू खाता घाटा

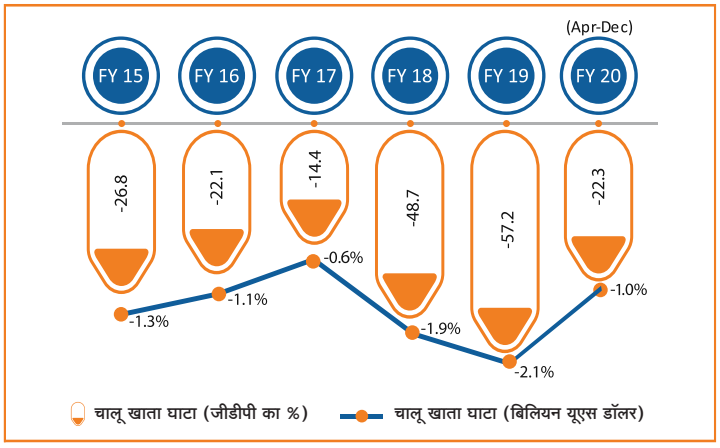

स्रोतः आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

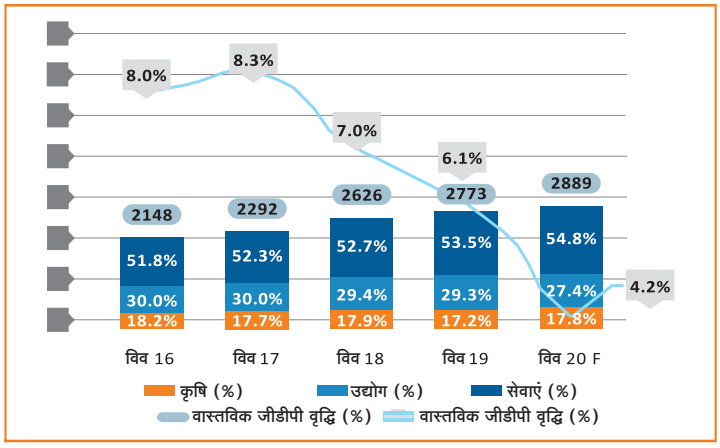

स्रोतः आईआईएफ एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नोटः पू. – पूर्वानुमान

आपकी डॉक्टोरल रिसर्च विश्व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।

और किस्मत साथ दे तो हमारे निर्णायकों पर भी।

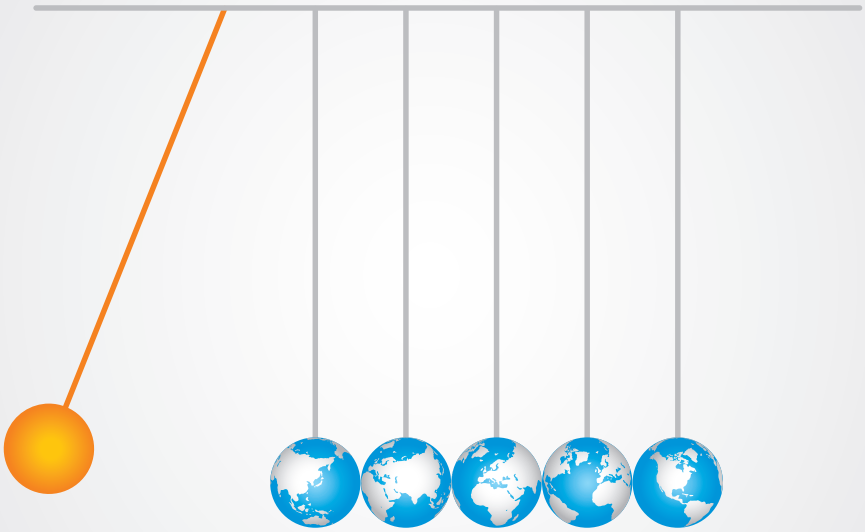

हमारे प्रतिष्ठित ईरा पुरस्कार 2020 के लिए आर्थिक शोध के क्षेत्र से आमंत्रित हैं डॉक्टरेट

एक्ज़िम बैंक ने आर्थिक शोध और विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार की स्थापना 1989 में की थी।

ईरा पुरस्कार 2020 के लिए ऐसे भारतीय नागरिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा भारत या विदेश से किसी शैक्षणिक संस्थान से डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी हो। यदि आपके पास है ऐसा शोध और डॉक्टरेट की उपाधि तो 30 सितंबर, 2020 तक हमें अपनी प्रविष्टि जरूर भेजें। पुरस्कार के रूप में 3.5 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए देखिए: **www.eximbankindia.in/Hindi/awards**

इंडिया एक्ज़िम बैंक
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार

CONCEPT

हमें फॉलो करें:

इंडिया एक्ज़िम बैंक